RNI No.: UPHIN/25/A1697
GARVI GUJARAT
गरवी गुजरात
लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 310
दि. 14.03.2026, शनिवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

असम में कांग्रेस पर भड़के पीएम मोदी, दी पंडित नेहरू से सीखने की नसीहत

(जीएनएस)।

असम में कुछ ही दिनों में विधानसभा चुनाव हैं। इससे पहले पीएम मोदी ने प्रदेश को कई बड़ी सौगात दी है। शुक्रवार (13 मार्च) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी में कई योजनाओं का शिलान्यास किया और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र की बीजेपी-नेतृत्व वाली एनडीए सरकार किसानों को मजबूत बनाने और देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है।

उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि संकट के समय भी कांग्रेस देश में भ्रम और गलत जानकारी फैलाने में लगी रहती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब देश विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तब विपक्ष को भी सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने कांग्रेस के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि वे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के 15 अगस्त के भाषण को सुनें, जिससे उन्हें कुछ सीखने को मिल सकता है।

'नेहरू से सीखें विपक्षी दल'

उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू ने अपने एक भाषण में कहा था कि दक्षिण और उत्तर कोरिया के बीच युद्ध का असर भारत में महंगाई पर पड़ रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि इतिहास से सीख लेकर देश को आगे बढ़ाने की जरूरत है। पीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि संकट के दौर में भी देश की सबसे पुरानी पार्टी सिर्फ भ्रम फैलाने में जुटी है।

असम को बताया विकास-मॉडल

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में असम के विकास का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज असम नॉर्थ-ईस्ट के नए भविष्य का मॉडल बनता जा रहा है। उन्होंने नॉर्थ-ईस्ट को 'अष्टलक्ष्मी' बताते हुए कहा कि यहां हो रहा विकास पूरे क्षेत्र को नई गति दे रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि असम में हो रहे विकास कार्यों का सकारात्मक असर पूरे उत्तर-पूर्वी क्षेत्र पर दिखाई दे रहा है और इससे क्षेत्र की आर्थिक और सामाजिक प्रगति को नई दिशा मिल रही है।

रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन को बताया मील का पत्थर

प्रधानमंत्री मोदी ने देश के रेलवे नेटवर्क में हुए बदलावों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि रेलवे को विदेशी संसाधनों पर निर्भरता से मुक्त करने और तेल आयात को कम करने के लिए पिछले एक दशक में बड़े कदम उठाए गए हैं उन्होंने बताया कि

पिछले 10 वर्षों में देश का पूरा रेलवे नेटवर्क इलेक्ट्रिफाई किया गया है। इस इलेक्ट्रिफिकेशन के कारण हर साल करीब 17 मिलियन लीटर डीजल की बचत हो रही है।

पीएम मोदी ने कहा कि यह कदम न केवल आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिल रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य देश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के हित, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और क्षेत्रीय विकास को प्राथमिकता देते हुए देश को तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

'विकास की जमीन भी तैयार करता है बुलडोजर', लखनऊ में ग्रीन कॉरिडोर के उद्घाटन पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

(जीएनएस)।

लखनऊ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को राजधानी में 1,519 करोड़ से तैयार ग्रीन कॉरिडोर योजना के दूसरे चरण का लोकार्पण और तीसरे व चौथे चरण का शिलान्यास किया। झूलेलाल वाटिका में आयोजित जनसभा में रक्षामंत्री ने बुलडोजर का मायने समझाते हुए कहा, मुख्यमंत्री योगी की ख्याति बुलडोजर बाबा की है। यूपी का बुलडोजर केवल माफियाओं व गुंडों को सबक सिखाने के लिए अवैध कब्जों को ही नहीं तोड़ता, बल्कि विकास की नई जमीन भी तैयार करता है, महत्वाकांक्षी ग्रीन

कॉरिडोर योजना इसका प्रमाण है।

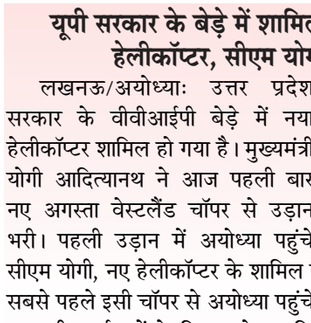

रक्षामंत्री बोले, लखनऊ की तहजीब की चर्चा दुनिया में होती रही है लेकिन, अब यहां के विकास की देश-दुनिया प्रशंसा कर रही है। अच्छा व रहने लायक शहर बनाने के लिए लखनऊ में सुविधाएं अचानक नहीं बढ़ीं, निरंतर विकास होने से अभूतपूर्व प्रगति हुई है। अक्टूबर 2025 में यूनेस्को की ओर से लखनऊ को मिले प्रतिष्ठित प्रमाणपत्र क्रिएटिव सिटी आफ गैस्ट्रोनामी का उल्लेख करते हुए कहा, यहां के खानपान की भी अब दुनिया दीवानी हो गई है।

यूपी व लखनऊ की सांस्कृतिक पहचान भी बनी है। उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस ने पाकिस्तान में तहलका मचा दिया था।

चुनाव से पहले सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने गिनाए सरकार के काम, पीएम मोदी पर कही खास बात

(जीएनएस)।

असम में चुनाव से पहले सियासी मंच सज गया है और सीएम खुद रोज कई सभाएं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुवाहाटी में एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व ने राज्य को बड़े सपने देखने की प्रेरणा दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और आशीर्वाद से असम ने विकास के नए लक्ष्यों को तय किया है। अब उन लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने असम के लोगों को यह विश्वास दिलाया है कि राज्य भी बड़े सपने देख सकता है और उन्हें पूरा कर सकता है। उन्होंने कहा कि पहले जो सपने सिर्फ कल्पना लगते थे, अब वे संकल्प में बदल चुके हैं। अब उन संकल्पों को सफलता में बदलने का दौर शुरू हो गया है।

सीएम ने की पीएम मोदी की तारीफ

हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि असम के लोगों की ओर से वे प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राज्य ने विकास की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इसका लाभ राज्य के लोगों को मिलेगा। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री के 'अ ङ्ग१ अ२२' वाले विचार का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक भाषण या नारा नहीं है, बल्कि आज असम के लोगों के लिए एक आदर्श और लक्ष्य बन चुका है।

'राज्य के विकास की रफ्तार रहेगी जारी'

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और असम की जनता मिलकर इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए काम करेगी।

संक्षिप्त समाचार

तमिलनाडु चुनाव के लिए डीएमके औरकेएमडीके का गठबंधन फाइनल, सीटों पर लगी मुहर

तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो गई हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन (DMK प्रमुख) और ई.आर. ईश्वरन (KMDK महासचिव) के बीच एक अहम बैठक हुई। इस बातचीत के बाद यह तय हुआ कि KMDK पार्टी इस बार 'सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस' गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी।

एलपीजी संकट पर हंगामा, सीईसी ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए नोटिस

(जीएनएस)।

संसद के बजट सत्र के दौरान शुक्रवार (13 मार्च) को भी जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा में एलपीजी संकट को लेकर विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी की। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने देश में एलपीजी गैस की कमी के मुद्दे पर चर्चा की मांग करते हुए सदन में विरोध प्रदर्शन किया। हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही बार-बार बाधित हुई। आखिरकार इसे सोमवार 16 मार्च सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दिया गया।

सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने एलपीजी संकट का मुद्दा उठाया। चर्चा की मांग करते हुए अपनी सीटों से उठकर वेल में पहुंच गए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी सांसदों को शांत कराने की कोशिश की। सदन की कार्यवाही चलाने के लिए कई बार शांत रहने की अपील की, लेकिन स्थिति सामान्य नहीं हो सकी।

कई बार स्थगित हुई लोकसभा

लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया। इसके बाद सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। जब दोबारा बैठक शुरू हुई तब भी विपक्ष अपने रुख पर कायम रहा और विरोध जारी रहा। इसके बाद कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक स्थगित किया गया। लगातार जारी गतिरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए टाल दी गई।

विपक्ष का CEC को हटाने का नोटिस

इस बीच विपक्ष ने एक और बड़ा

मुद्दा उठाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग की। विपक्षी दलों ने दोनों सदनों में इस संबंध में नोटिस दिया है। बताया जा रहा है कि इस नोटिस पर करीब 190 सांसदों के हस्ताक्षर हैं। विपक्ष का आरोप है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपने पद का निष्पक्षता से निर्वहन नहीं किया है। विशेष रूप से तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने उन पर पक्षपात और दुर्व्यवहार के आरोप लगाए हैं। लोकसभा सचिवालय को इस संबंध में औपचारिक नोटिस मिल चुका है।

सरकार ने विपक्ष पर साधा निशाना

लोकसभा में हंगामे के बीच केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष और खास तौर पर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष संसद की कार्यवाही को बाधित कर रहा है और गंभीर मुद्दों पर चर्चा से बच रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का काम केवल भ्रम फैलाना है और वे अक्सर विदेश नीति और अन्य मुद्दों पर गलत जानकारी फैलाते हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि गंभीर राष्ट्रीय मुद्दों पर विपक्ष का रवैया जिम्मेदार नहीं है।

इसी बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में 'अनुदान की अनुपूरक मांगें 2025-26 (दूसरा बैच)' पर हुई बहस का जवाब दिया। उन्होंने बताया कि जब ट्ऋ्छफ्एऋअ-श्इ-ॠ फ्ङ्खअट-ॠ बिल लाया गया था तब इसके लिए 95,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था, जिसे 1 अप्रैल से लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अनुपूरक मांगों के तहत अतिरिक्त 30,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है और सरकार इस योजना के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा कर रही है।

राज्यसभा में सामान्य रही कार्यवाही

जहां लोकसभा में हंगामे के कारण कार्यवाही बाधित रही, वहीं राज्यसभा की कार्यवाही अपेक्षाकृत सुचारू रूप से चलती रही। हालांकि विपक्ष ने वहां भी उएउ को हटाने के मुद्दे पर नोटिस दिया है। शुक्रवार को संसद में राजनीतिक टकराव का माहौल देखने को मिला। एलपीजी संकट, चुनाव आयोग से जुड़े विवाद और सरकार-विपक्ष के आरोप-प्रत्यारोप के कारण लोकसभा में कामकाज प्रभावित रहा।

यूपी सरकार के बेड़े में शामिल हुआ नया अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर, सीएम योगी ने भरी पहली उड़ान

लखनऊ/अयोध्याः उत्तर प्रदेश सरकार के वीवीआईपी बेड़े में नया हेलीकॉप्टर शामिल हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यानथ ने आज पहली बार नए अगस्ता वेस्टलैंड चॉपर से उड़ान भरी। पहली उड़ान में अयोध्या पहुंचे सीएम योगी, नए हेलीकॉप्टर के शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले इसी चॉपर से अयोध्या पहुंचे। यह हेलीकॉप्टर वीवीआईपी यात्रा और सरकारी कार्यक्रमों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।

आधुनिक सुविधाओं से लैस है हेलीकॉप्टर

सरकारी बेड़े में शामिल यह ॲ४२३ंही२३ 'ल्ल का हेलीकॉप्टर आधुनिक तकनीक और सुरक्षा सुविधाओं से लैस है। इससे मुख्यमंत्री और अन्य वीवीआईपी की यात्रा अधिक सुरक्षित और तेज हो सकेगी।

सरकारी बेड़े की ताकत बढ़ी

नए हेलीकॉप्टर के शामिल होने से उत्तर प्रदेश सरकार के विमानन बेड़े की क्षमता बढ़ गई है। इससे प्रशासनिक और आपातकालीन कार्यों में भी तेजी आएगी।

मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष के बीच ईरान के राजदूत मोहम्मद फतहाली बोले, 'भारत और ईरान के हित और दर्द दोनों एक जैसे'

(जीएनएस)।

मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष के बीच ईरान बार-बार भारत से अपने मजबूत रिश्तों की दुहाई दे रहा है। नई दिल्ली में ईरान के राजदूत मोहम्मद फतहाली (टर्ङ्में ऋङ्कॅ) ने भारत और ईरान के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच साझा हित और विश्वास मौजूद हैं। इसके आधार पर द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाया जा रहा है।

राजदूत मोहम्मद फतहाली ने कहा कि भारत और ईरान कई मुद्दों पर समान दृष्टिकोण रखते हैं। क्षेत्रीय स्तर पर भी दोनों देशों के हित जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि जब एक देश कठिनाई में होता है तो दूसरा देश उसकी मदद करता है और यही साझेदारी की असली भावना है।

दोनों देशों को बताया मजबूत साझेदार

उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने कई मौकों पर ईरान का समर्थन किया है और इसी तरह ईरान भी भारत के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उनके

अनुसार, दोनों देशों के बीच संबंध केवल कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों से भी जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल हालात में दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास मजबूत होना चाहिए।

'स्थिरता के लिए मजबूत रिश्ते जरूरी'

ईरानी राजदूत ने कहा कि क्षेत्र में स्थिरता और विकास के लिए भारत और ईरान का सहयोग महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों ने भारत स्थित ईरानी दूतावास को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। दोनों देशों की सरकारों के बीच सहयोग को और मजबूत करने के लिए सक्रिय रूप से काम किया जाए।

फतहाली के अनुसार, दूतावास का मुख्य उद्देश्य भारत और ईरान के बीच विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारी को बढ़ावा देना है। इसमें व्यापार, निवेश, ऊर्जा, कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय सहयोग जैसे कई अहम क्षेत्र शामिल हैं।

भविष्य में भी मजबूत रहेंगे भारत-ईरान के रिश्ते

उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध लंबे समय से मजबूत रहे हैं और भविष्य में इन्हें और मजबूत बनाने के लिए कई पहल की जा रही हैं। ईरान और भारत के बीच बढ़ता सहयोग क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

राजदूत ने यह भी कहा कि दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास और साझा हितों के आधार पर सहयोग को आगे बढ़ाया जाएगा।

विदेश जाने और लाखों रुपए कमाने का युवाओं के लिए मौका, जानिए धामी सरकार की इस कमाल की योजना के बारे में

(जीएनएस)।

विदेशी भाषाएं सीखकर विभिन्न देशों में नौकरी करने के इच्छुक छात्र-छात्राओं को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने अल्मोड़ा में लैंग्वेज ट्रेनिंग सेंटर खोलने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना के अंतर्गत वर्तमान में सिर्फ एक सेंटर है।

यह सेंटर वर्ष 2023 से देहरादून में संचालित है। अल्मोड़ा में सेंटर खुलने के बाद इस तरह के सेंटरों की प्रदेश में संख्या दो हो जाएगी। राज्य सरकार ने वर्ष 2023 से मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना को शुरू किया है।

इसके अंतर्गत देहरादून में पहला लैंग्वेज ट्रेनिंग सेंटर खोला गया है, जिसमें विभिन्न भाषाओं का बच्चों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और यहीं से उनकी नौकरी की व्यवस्था की जा रही है। जो कि लाखों में भी कमा रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी ने विभाग को निर्देश दिए हैं कि इन सेंटरों की संख्या बढ़ाई जाए। ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को

इसका लाभ मिल सके।

शुक्रवार को विधानसभा के बजट सत्र के पांचवें दिन कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने सरकार की ओर से अल्मोड़ा में लैंग्वेज ट्रेनिंग सेंटर खोलने की घोषणा की। इस योजना में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को लाभ पहुंचाने को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काफी गंभीर है।

यही वजह है कि इस योजना में ट्रेनिंग का जो बजट सिर्फ 75 लाख रुपए का था, उसे इस बार 3.3 करोड़ रुपए कर दिया गया है। कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि मुख्यमंत्री की सकारात्मक सोच के चलते अब और ज्यादा बच्चों को ट्रेनिंग का लाभ मिल पाएगा।

147 -बच्चों को अभी तक दिया गया विदेशी भाषा का प्रशिक्षण

92- बच्चों की विभिन्न देशों में अभी तक लग चुकी है नौकरी

08-से 10 माह का बच्चों को दिया जाता है सेंटर में प्रशिक्षण

16 -अधिकृत एजेंसियों के माध्यम से दिया जा रहा है प्रशिक्षण

10-और बच्चों के लिए सऊदी अरब में है नौकरी का प्रस्ताव

सऊदी अरब में सेवारत 30 बच्चे सुरक्षित

पश्चिम एशिया में युद्ध के हालात के बीच राज्य सरकार उन लोगों की भी पूरी चिंता कर रही है, जिन्हें इस योजना के माध्यम से विदेशों में नौकरी मिली है। सदन में कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि सऊदी अरब में सेवारत लोगों से बात हुई है और वे पूरी तरह से सुरक्षित हैं।

सम्पादकीय

राज्यसभा की सदस्यता के लिये नीतीश के नामांकन दाखिल करने के बाद से ही बिहार नये मुख्यमंत्री पर कयास जारी

नीतीश कुमार का नेतृत्व चट्टान की तरह अभेद्य रहा और भाजपा के साथ रहने का प्रतिफल है कि वह बिहार के सर्वोच्च नेता बने हुए हैं। भले ही वह मुख्यमंत्री पद छोड़ दें लेकिन बिहार पर उनकी पकड़ बनी रहने वाली है। नीतीश कुमार चले राज्यसभा की ओर, बिहार का नया मुख्यमंत्री कौन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर चौंकाने वाला पैसला लिया और राज्यसभा की सदस्यता के लिये अपना नामांकन दाखिल किया है। इस पैसले ने राजनीतिक हल्कों में चर्चा की पोटली खोल दी है, वुछ इसे भविष्य के लिये नया राजनीतिक दांव मान रहे हैं तो वुछ यह कह रहे हैं नीतीश कुमार ने अपने बेटे निशांत कुमार को राजनीति में लाकर नया संदेश दिया है। बिहार की सत्ता छोड़ने से पहले नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के अगले चरण के लिये निकल पडे हैं। नीतीश ने सुपौल को 569.36 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। दरअसल नीतीश कुमार पांच दिन में 10 जिलों का दौरा करेंगे जो 14 मार्च तक चलेगा। इस दौरे की जद में राज्य के सीमांचल और कोसी के इलाके रहेंगे। इस दौरान वह स्थानीय प्रशासन के साथ समीक्षा बैठवें करेंगे और जनहित की योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन करेंगे। नेतृत्व परिवर्तन की चचाओं के बीच अब एक ही परिवार से जुड़ी दो अलग-अलग राजनीतिक यात्राओं की तैयारी की। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी 'समृद्धि यात्रा' के अंतिम चरण पर निकल पडे हैं तो दूसरी ओर उनके बेटे निशांत कुमार भी अपनी पहली राजनीतिक यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। पूरे घटनाव्रम पर राजनीतिक दलों की प्रतिव्रियाएं भी सामने आईं हैं। भारतीय जनता पाटा बिहार में जनता दल यूनाइटेड के साथ मिलकर सरकार चला रही है और उसने कहा कि निशांत कुमार की यात्रा पाटा का आंतरिक मामला है। पाटा नेताओं का कहना है कि नीतीश कुमार की यात्राएं हमेशा से जनता से सीधे जुड़ने का एक प्रभावी तरीका रही हैं। विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल की अलग सोच है। पाटा का कहना है कि नीतीश कुमार की यात्रा का मकसद यह दिखाना है कि मुख्यमंत्री पद छोड़ने का पैसला उन्होंने अपनी इच्छा से लिया है न कि किसी दबाव में। विपक्ष का यह भी कहना है कि राजनीति और प्रशासन को समझने के लिए निशांत कुमार को अलग से यात्रा करने के बजाय अपने पिता के साथ समृद्धि यात्रा में शामिल होना चाहिए था। वुल मिलाकर बिहार की राजनीति में इन दोनों यात्राओं को काफी अहम माना जा रहा है। एक तरफ यह नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत को मजबूत करने का प्रयास है तो दूसरी ओर निशांत कुमार के राजनीतिक सफर की शुरूआत के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। ऐसे में एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि उत्तर प्रदेश में भगवान श्रीराम का भव्य मंदिर बन चुका है। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मिथिला की बेटी जानकी माता के नाम पर एक भव्य मंदिर का निर्माण शुरू करा दिया है। देश में सांस्वृतिक एवं धरमिक पहचान को मजबूत किया जा रहा है। दरअसल नीतीश कुमार विकास के पर्याय बन चुके हैं। यह भी सत्य है कि उनकी दूरदशा नीतियों के कारण आज बिहार के किसी भी कोने से पटना चार से पांच घंटे में पहुंचा जा सकता है। जनता दल यूनाइटेड ने बिहार में सत्ता में बने रहने के लिये हर तरह के प्रयोग किये, कभी भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लडा तो कभी उसके साथ सरकार बनाईं। उन्होंने विपक्ष का हाथ थामा और राष्ट्रीय जनता दल की अगुआईवाले महागठबंधन के साथ मिलकर भी सरकार बनाईं और उनकी मेहरबानी के कारण ही राजद नेता तेजस्वी यादव को उपमुख्यमंत्री बने। एक बारगी यह लगने लगा था कि तेजस्वी यादव बिहार की अगली पीढी के मुख्यमंत्री बन जायेंगे लेकिन नीतीश के फिर पासा पलटने उनका सारा गणित गड़बड़ा गया। समय ने तेजी से करवट लिया और जनता दल यूनाइटेड ने भाजपा का दामन फिर से थाम लिया। भाजपा को नीतीश कुमार का साथ खूब भाया और वह बिहार में सबसे बडे राजनीतिक दल के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने में सफल रही। यह तय माना जा रहा है कि बिहार में पहली बार भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा। इस बात की अटकलें जा लगने लगी हैं कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, उपमुख्यमंत्री में कोई पदोन्नत किया जायेगा, कोई नया चेहरा होगा या कोई महिला मुख्यमंत्री बनेगी।

ईरान की जंग से बाहर होना चाहते हैं ट्रम्प! ऑपरेशन एपिक फ्यूरी बना सिरदर्द, इजरायल फंसेगा अकेला?

(जीएनएस)।

मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति Donald Trump के बार-बार बदलते बयान से अब अमेरिका ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया ऊब गई है। उनके बयानों से ऐसा लग रहा है कि इस जंग की शुरूआत कर के बुरे फंस गए और अब बस निकलना चाहते हैं। अपने बयानों में कभी वह कहते हैं कि अमेरिका जंग जीत चुका है, तो कभी कहते हैं कि अभी ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है।

इसके पीछे व्हाइट हाउस के अंदर चल रही एक राजनीतिक खींचतान बताई जा रही है। जिसके चक्कर में ट्रंप का ही खेमा दो धड़ों में बंटा दिख रहा है। असल में ट्रंप के कई सलाहकार और राजनीतिक सहयोगी इस बात पर अलग-अलग राय दे रहे हैं कि जंग में जीत का शंखनाद कब और कैसे बजाया जाए। वहीं दूसरी तरफ यह जंग का ये रायता सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहा और इसने पूरे मिडिल ईस्ट को लपेटे में ले लिया है।

ट्रंप के सलाहकारों में भयंकर मतभेद

ट्रंप के एक सलाहकार और इस मामले से जुड़े अन्य लोगों के मुताबिक व्हाइट हाउस के अंदर इस युद्ध को लेकर काफी मतभेद हैं। कुछ अधिकारी राष्ट्रपति को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमलों की वजह से गैसोलीन की कीमतें बढ़ जाती हैं, तो इसका घरेलू राजनीति पर बड़ा निगेटिव असर पड़ सकता है। दूसरी तरफ कुछ कट्टरपंथी नेता चाहते हैं कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई और ज्यादा तेज की जाए ताकि उसे पूरी तरह कमजोर किया जा सके।

व्हाइट हाउस से बाहर आने लगी बातें

समाचार एजेंसी Reuters की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन के अंदर हो रही इन चचाओं की पहले कभी इतनी खुलकर रिपोर्टिंग नहीं हुई थी। यह स्थिति खास इसलिए भी है क्योंकि यह अभियान 2003 के IrÔq WÔr के बाद अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अभियान माना जा रहा है। यानी अमेरिका के भीतर ही इस युद्ध को लेकर स्पष्ट रणनीति पर पूरी तरह सहमति नहीं बन पाई है।

ट्रंप के लिए राजनीतिक दांव बहुत बड़ा

इस पूरे घटनाक्रम से यह साफ है कि इस युद्ध में ट्रंप के लिए राजनीतिक दांव बहुत ऊंचे हैं। उन्होंने पिछले साल चुनाव प्रचार के दौरान वादा किया था कि अमेरिका को मूर्खतापूर्ण मिलिट्री दखलों से दूर रखा जाएगा। यहां ट्रंप बाइडेन के कार्यकाल में छिड़े रूस-यूक्रेन और इजरायल-हमास युद्ध की ओर इशारा कर रहे थे। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा, सत्ता संभालने के लगभग दो हफ्ते बाद ही अमेरिका एक ऐसे युद्ध में शामिल हो गया जिसने वैश्विक वित्तीय बाजारों को हिला दिया और अंतरराष्ट्रीय तेल व्यापार को भी प्रभावित कर दिया।

युद्ध के नए नाम खोजने की कोशिशें

जब 28 फरवरी को युद्ध शुरू हुआ था, तब इसके लक्ष्य काफी बड़े बताए गए थे। लेकिन हाल के दिनों में ट्रंप इस संघर्ष को एक "सीमित सैन्य अभियान" यानी लिमिटेड मिलिट्री ऑपरेशन्स के रूप में पेश कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस ऑपरेशन के अधिकांश लक्ष्य पहले ही पूरे हो चुके हैं। इस बदलाव से साफ दिखता है कि व्हाइट हाउस के अंदर रणनीति को लेकर लगातार मंथन चल रहा है।

तेल-गैस के बाजारों में भी दिख रहा असर

ट्रंप के बदलते बयानों का असर सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है। तेल और गैस के बाजार भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। तेल और गैस की कीमतें उनके बयानों के बाद कभी तेजी से ऊपर जाती हैं तो कभी नीचे गिर जाती हैं। यानी निवेशकों और बाजार को भी साफ संकेत नहीं मिल पा रहा कि युद्ध कितने समय तक चलेगा।

कभी हां- कभी ना

हाल ही में केंटकी में एक चुनावी रैली के दौरान ट्रंप ने पहले कहा कि "हमने युद्ध जीत लिया है। लेकिन कुछ ही देर बाद उन्होंने अपना बयान बदलते हुए कहा कि "हम जल्दी बाहर नहीं निकलना चाहते। हमें काम पूरा करना होगा।" इस तरह के बयान यह

दिखाते हैं कि ट्रंप अभी तक स्पष्ट रूप से यह तय नहीं कर पाए हैं कि इस युद्ध को अपनी जनता के सामने कैसे परोसें, फिर दुनिया का तो भूल ही जाइए।

सलाहकार दे रहे ट्रंप को चेतावनी

अमेरिका के आर्थिक सलाहकारों और अधिकारियों- जिनमें ट्रेजरी डिपार्टमेंट और नेशनल इकॉनोमिक काउंसिलर के सदस्य शामिल हैं, इन सब लोगों ने ट्रंप को चेतावनी दी है। उनका कहना है कि अगर तेल की कीमतें तेजी से बढ़ती हैं और गैसोलीन महंगा होता है, तो जनता का युद्ध के प्रति समर्थन तेजी से कम हो सकता है। इन चचाओं की जानकारी नाम न छापने की शर्त पर एक सलाहकार और दो अन्य सूत्रों ने दी।

राजनीतिक टीम की चिंता

ट्रंप की राजनीतिक टीम भी इसी तरह की चिंता जता रही है। इनमें चीफ ऑफ स्टाफ र४३ी ह्वी२ और डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ खौंर इ'१ शामिल हैं। इन नेताओं का मानना है कि ट्रंप को जीत की परिभाषा सीमित रखनी चाहिए। जैसे कि यह कहना कि सेना के ईरान में चल रहे ऑपरेशन लगभग खत्म होने वाला है। न कि जीत का दावा करना चाहिए।

कट्टरपंथी नेताओं का दबाव

लेकिन दूसरी तरफ कुछ रिपब्लिकन नेता चाहते हैं कि ईरान के खिलाफ सैन्य दबाव जारी रखा जाए। इस समूह में अमेरिकी सीनेटर Lindsey Graham और Tom Cotton शामिल हैं। इसके अलावा मीडिया कमेंटेटर भी इसी तरह की राय रखते हैं। उन नेताओं का तर्क भी जान लेते हैं। इन नेताओं का कहना है कि अमेरिका को ईरान को न्यूक्लियर हथियार हासिल करने से रोकना चाहिए। साथ ही ये भी कि अमेरिकी सैनिकों और शिपिंग पर हुए हमलों का मजबूत और सख्त जवाब देना जरूरी है।

ट्रंप के समर्थकों का भी दबाव

एक तीसरा गुट भी है, ट्रंप का कट्टर समर्थकों का गुट। इनें आप ट्रंप के अंधभक्त भी कह सकते हैं। इसमें रणनीतिकार Steve Bannfon और टीवी होस्ट Tucker Carlson जैसे लोग शामिल हैं। ये लोग ट्रंप से कह रहे हैं कि अमेरिका को मिडिल ईस्ट के एक और लंबे युद्ध में नहीं फंसना चाहिए। ये इशारा कुछ हद तक 1955 से लेकर 1975 तक चले अमेरिका-वियतनाम युद्ध की तरफ है, जहां अमेरिका ने 20 सालों तक जंग लड़ी लेकिन अंत में सिर्फ ठेंगा हाथ लगा।

तीन अलग-अलग संदेश देने की रणनीति

ट्रंप के एक सलाहकार के मुताबिक राष्ट्रपति एक तरह से तीन अलग-अलग संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। कट्टरपंथी नेताओं को लगता है कि सैन्य अभियान जारी रहेगा। बाजार को यह संकेत दिया जा रहा है कि युद्ध जल्दी खत्म हो सकता है। और उनके समर्थकों को बताया जा रहा है कि संघर्ष ज्यादा नहीं फैलेगा। और यही ट्रंप की सबसे बड़ी गलती है कि ट्रंप तीनों पक्षों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं।

व्हाइट हाउस अलग रास्ते पर

जब इस रिपोर्ट पर टिप्पणी मांगी गई तो व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव KÔroli»»fe LeÔvitt ने इसे गुमनाम सोर्सेस की अटकलें बताया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति कई लोगों की राय सुनते हैं लेकिन अंतिम फैसला वही लेते हैं। मतलब जवाब वो भी नहीं दे पाईं।

ऑपरेशन एपिक फ्यूरी बना एपिक सिरदर्द

लेविट ने कहा कि राष्ट्रपति की पूरी टीम का ध्यान "OperÔtio»»f Epic Fury" के मकसद को पूरा करने पर है। यानी प्रशासन का आधिकारिक संदेश यही है कि अभियान अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ठीक से देखें तो लेविट एक चौथी बात कह कर चली गईं।

भाईजान भूल गए 'मकसद'

जब अमेरिका ने यह युद्ध शुरू किया था तब उसके मकसद पूरी तरह साफ नहीं थे। कभी कहा गया कि यह ईरान के संभावित हमले को रोकने के लिए है, कभी कहा गया कि उसका न्यूक्लियर कार्यक्रम खत्म करना है, और कभी यह भी कहा गया कि ईरान की रिजीम चेंज करना है।

बाजारों को संभाल रहे ट्रंप

अब जब युद्ध लंबा खिंचता दिख रहा है, ट्रंप के आर्थिक सलाहकार बाजारों को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। वे यह संदेश दे रहे हैं कि युद्ध ज्यादा लंबा नहीं चलेगा और तेल-गैस की कीमतों में बढ़ोतरी अस्थायी है।

हार को जीत बताने की जिम्मेदारी

सूत्रों के मुताबिक कुछ सहयोगियों ने ट्रंप को सलाह दी है कि युद्ध को ऐसी स्थिति में खत्म किया जाए जिसे सैन्य जीत कहा जा सके। फिर चाहे, ईरान की लीडरशिप पूरी तरह खत्म न हो और उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम भी पूरी तरह से बर्बाद न हुआ हो। याद रहे, ऐसी ही जीत का दावा अमेरिका पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हेनरी किसिंजर ने वियतनाम में पीठ दिखाकर लौटते वक्त किया था। फिलहाल अमेरिका के इस युद्ध में 7 सैनिक मारे जा चुके हैं और 4 और सैनिक हाल ही में हुई ङउ-135 एयरक्राफ्ट की घटना में हताहत होने की खबर आ गई है।

अमेरिकी राजनीति में ट्रंप की फजीहत

अगर इस वजह से अमेरिका में गैस की कीमतें बढ़ती हैं तो नवंबर के मिड टर्म इलेक्शन में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी पर राजनीतिक दबाव बढ़ सकता है। इसी से ट्रंप की फजीहत भी हो सकती है। ट्रंप के कुछ करीबियों ने उन्हें वेनेजुएला की तर्ज पर जीत का भरोसा दिलाया था पर ऐसा दूर-दूर तक नहीं हो रहा है।

लंबा चला युद्ध तो अमेरिका का नुकसान

वहीं एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर युद्ध लंबा चला, अमेरिकी सैनिकों की मौत बढ़ी और आर्थिक लागत ज्यादा हुई, तो ट्रंप के समर्थकों का समर्थन भी धीरे-धीरे कम हो सकता है। जो इतिहास में ट्रंप को आबाद के नाम पर बर्बाद करने वाले राष्ट्रपति के तौर पर याद रखवा सकता है।

कानपुर : साली को 'सपने में छेड़ने' की सजा जेल? 7 साल बाद एयरफोर्स कर्मी कोर्ट से क्यों और कैसे हुआ बरी?

(जीएनएस)।

कानपुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां नाबालिग साली से छेड़छाड़ के आरोप में फंसे एक एयरफोर्स कर्मी को करीब सात साल बाद अदालत से राहत मिल गई। कोर्ट ने सभी आरोपों से बरी कर दिया, क्योंकि पीड़िता ने अपने बयान में कहा कि उसे घटना सच में नहीं, बल्कि सपने में महसूस हुई थी।

इस मामले में आरोप लगने के बाद एयरफोर्स कर्मी को 19 दिन तक जेल में रहना पड़ा था। लंबी सुनवाई और गवाहों के बयान के बाद विशेष POCSO कोर्ट ने सबूतों के अभाव में आरोपी को दोषमुक्त कर दिया। लड़की ने खुद कोर्ट में कहा- 'सपने में ऐसा महसूस हुआ था, असल में कुछ नहीं हुआ। दवा की वजह से भ्रम हो गया था।' यह पूरा मामला ससुराल की प्रॉपर्टी विवाद का नतीजा था। आइए स्टेप-बाय-स्टेप समझते हैं कि कैसे एक सपना 7 साल तक जिंदगी बर्बाद कर सकता है...

साली ने लगाया जीजा का छेड़छाड़ का आरोप

मामले की शुरूआत 2019 में हुई थी। बिठूर के रहने वाले एयरफोर्स कर्मी की शादी 10 फरवरी 2019 को बिधनू इलाके की एक युवती से हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद वह अपनी

पत्नी को लेने ससुराल गया था। उस समय उसकी नाबालिग साली भी उनके साथ आई थी।

एफआईआर के अनुसार, 8 मार्च 2019 की रात करीब 9 बजे लड़की अचानक जोर-जोर से चिल्लाने लगी। उसकी बड़ी बहन जब कमरे में पहुंची तो उसने आरोप लगाया कि उसके जीजा ने उसे पकड़ लिया और छेड़छाड़ की। इसके बाद परिवार ने पुलिस को सूचना दी। हालांकि उस समय आरोपी अपने पिता के साथ वहां से चला गया था। बाद में लड़की के पिता की शिकायत पर करीब पांच महीने बाद 3 अगस्त 2019 को नौबस्ता थाने में मामला दर्ज कराया गया।

19 दिन जीजा जेल में, जमानत पर मिली रिहाई

पुलिस ने जांच के बाद 29 सितंबर 2019 को एयरफोर्स कर्मी को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। करीब 19 दिन जेल में रहने के बाद 17 अक्टूबर को उसे जमानत मिल गई। जांच के दौरान पुलिस ने पीड़िता के शुरूआती बयान के आधार पर चार्जशीट दाखिल की। आरोपी के खिलाफ मारपीट, बदनामी, छेड़छाड़ और लैंगिक हमले जैसे आरोप लगाए गए और पॉक्सो कोर्ट में मुकदमा शुरू हुआ।

7 साल बाद साली ने जीजा को बताया बेगुनाह

मामले में बड़ा मोड़ तब आया, जब दिसंबर 2021 में कोर्ट में पीड़िता के बयान दर्ज हुए। उसने अदालत को बताया कि घटना की रात वह एंटीबायोटिक दवा लेकर सो रही थी और आधी नींद में थी। उसी दौरान उसे सपने में ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने उसे पकड़ लिया है, जिसे उसने अपने जीजा समझ लिया और शोर मचा दिया।

लड़की ने अदालत में कहा कि वास्तव में उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई थी, बल्कि यह सब भ्रम की वजह से हुआ था। बाद में उसके पिता और बड़ी बहन ने भी अदालत में कहा कि गलतफहमी में रिपोर्ट दर्ज करा दी गई थी।

इन बयानों के बाद अदालत ने पूरे मामले की समीक्षा की और पाया कि आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य मौजूद नहीं हैं।

ओटीटी पर कहां देखें 'बॉर्डर 2'? अब घर बैठे लें सनी देओल की फिल्म का मजा

(जीएनएस)।

बॉलीवुड के दमदार एक्टर सनी देओल जब भी बड़े पर्दे पर वापसी करते हैं, तो फैंस का उत्साह देखने लायक होता है। इस साल भी उन्होंने अपनी सुपरहिट फिल्म 'बॉर्डर' के सीक्वल 'बॉर्डर 2' के जरिए सिनेमाघरों में जबरदस्त धमाल मचाया था।

ओटीटी पर रिलीज होने वाली है 'बॉर्डर 2'

23 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस फिल्म को दर्शकों ने खूब पसंद किया और बॉक्स ऑफिस पर इसने छप्पड़फाड़ कमाई की। अब थिएटर में सफलता हासिल करने के बाद ये फिल्म जल्द ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज होने जा रही है।

कहां और कब देख सकेंगे फिल्म 'बॉर्डर 2'?

-डायरेक्टर अनुराग सिंह के निर्देशन में बनी फिल्म 'बॉर्डर 2' को जो लोग थिएटर में देखने से चूंक गए थे अब वो इसका मजा घर बैठे ही ले पाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सनी देओल की सुपरहिट फिल्म 'बॉर्डर 2' आगामी 20 मार्च 2026 से ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स (ठी३ι'७) पर स्ट्रीम की जाएगी।

अ'२ङ्ग र्फ़ी

'मुसलमानों से ज्यादा तो हिंदू मर्द ही', बॉलीवुड की फेमस मुस्लिम एक्ट्रेस का बड़ा बयान, धर्म पर ये क्या

कहा?

'मुसलमानों से ज्यादा तो हिंदू मर्द ही', बॉलीवुड की फेमस मुस्लिम एक्ट्रेस का बड़ा बयान, धर्म पर ये क्या कहा?

-इस फिल्म में सनी देओल के साथ कई मशहूर स्टार्स नजर आए हैं। फिल्म में वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी ने अहम भूमिकाएं निभाई है। चारों कलाकारों की दमदार एक्टिंग की दर्शकों और समीक्षकों ने खूब तारीफ की थी।

बॉक्स ऑफिस पर 'बॉर्डर 2' का धमाका

-आपको बता दें कि साल 1997 में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म 'बॉर्डर' के निर्देशक जेपी दत्ता थे। फिल्म 'बॉर्डर' को उस दौर की सबसे यादगार युद्ध मूवीज में गिना जाता है।

-वहीं 'बॉर्डर' की सीक्वल 'बॉर्डर 2' को जेपी दत्ता की बेटी निधि दत्ता और भूषण कुमार ने मिलकर प्रोड्यूस किया है। बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म ने दुनियाभर में करीब 449.65 करोड़ रुपये की कमाई की है, जो इसे साल की बड़ी हिट फिल्मों में शामिल करता है।

सनी देओल के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स

-सनी देओल के साल 2026 काफी बिजी रहने वाला है। वह एक नहीं बल्कि कई बड़ी फिल्मों में नजर आने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी अपकमिंग फिल्म 'गबरू' आगामी 8 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

-इसके बाद सनी देओल फिल्म 'लाहौर 1947' में दिखाई देंगे जिसे आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस के तहत बनाया गया है और ये मूवी 14 अगस्त 2026 को थिएटर्स में रिलीज होगी।

-इतना ही नहीं दिवाली 2026 पर रिलीज होने वाली फिल्म 'रामायण-पार्ट 1' में भी सनी देओल भगवान हनुमान के किरदार में नजर आएंगे। इस फिल्म में उनके साथ बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर ने काम किया है जो कि प्रभु श्रीराम के रोल में दिखाई देंगे।

-इसके अलावा सनी देओल और अक्षय खन्ना की फिल्म 'इक्का' (क्र्") भी काफी चर्चा में है, जिसे सीधे ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाएगा।

तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज के लिए साल 2026 यादगार रहा

(जीएनएस)।

भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज के लिए साल 2026 यादगार रहा है। एक तरफ टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीतकर इतिहास रचा है। दूसरी तरफ 13 मार्च यानी शुक्रवार को सिराज ने अपना 32वां जन्मदिन मनाया। इस खास मौके पर दिग्गज गायिका आशा भोसले की पोती और सोशल मीडिया पर्सनैलिटी जनाई भोसले का पोस्ट चर्चा का विषय बन गया है।

जनाई भोसले ने इंस्टाग्राम पर किया पोस्ट

जनाई भोसले ने इंस्टाग्राम पर सिराज के लिए एक दिल छू लेने वाली पोस्ट शेयर की। उन्होंने सिराज को अपना 'सबसे पसंदीदा इंसान' (ट८ ऋॅ‌ङ्ग४१३ी२३ ढी१२ङ्गल्ल) बताते हुए उनके प्रति अपना स्नेह और सम्मान व्यक्त किया। वर्ल्ड कप की ऐतिहासिक जीत के तुरंत बाद आए इस संदेश ने फैंस का ध्यान

अपनी ओर खींच लिया। जनाई ने अपनी पोस्ट में सिराज की उपलब्धि पर गर्व जताते हुए उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं।

मोहम्मद सिराज ने यूएसए के खिलाफ किया था कमाल

मोहम्मद सिराज इस पूरे टूनार्मेंट में शानदार लय में नजर आए। विशेष रूप से अमेरिका (वरअ) के खिलाफ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मैच में उन्होंने 29 रन देकर 3 विकेट चटकाए, जिसने भारत की जीत की नींव रखी थी। उस समय भी जनाई ने एक स्पेशल नोट लिखकर सिराज का हौसला बढ़ाया था। सिराज के इस प्रदर्शन और वर्ल्ड कप फाइनल में उनकी भूमिका ने उन्हें भारतीय गेंदबाजी आक्रमण का एक अनिवार्य हिस्सा साबित कर दिया है।

पुरानी है जनाई और सिराज की दोस्ती

जनाई और सिराज की दोस्ती पिछले साल भी सुर्खियों में रही थी, जब जनाई के जन्मदिन की कुछ तस्वीरें वायरल हुई थीं। हालांकि, दोनों ने हमेशा एक-दूसरे को अच्छा दोस्त और पारिवारिक सदस्य बताया है। पिछले साल रक्षाबंधन के अवसर पर जनाई द्वारा सिराज को राखी बांधने की तस्वीरों ने उन सभी अटकलों पर विराम लगा दिया था जो उनके रिश्ते को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही थीं।

कौन हैं सायली सुर्वे? मिसेज इंडिया अर्थ 2019, हिंदू धर्म में की वापसी

(जीएनएस)।

2019 में मिस इंडिया अर्थ का खिताब जीतने वाली सायली ने अपने पति आतिफ तासे पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। जानकारी के मुताबिक, उन्होंने अपने परिवार की इच्छा के खिलाफ जाकर मीरा-भाईंदर के कारोबारी आतिफ तासे से प्रेम विवाह किया था। शादी के लिए उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार किया था, जिसके बाद उनका नाम बदलकर अतेजा तासे रख दिया गया। अब हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सायली ने आरोप लगाया है कि शादी के बाद उनके साथ जबरन धर्म परिवर्तन, मारपीट और गाली-गलौज जैसी घटनाएं हुईं। सायली सुर्वे के इन आरोपों ने लोगों को चौंका दिया है और मामला अब चर्चा का विषय बन गया है।

सायली सुर्वे?

सायली सुर्वे महाराष्ट्र के पिंपरी-चिंचवड क्षेत्र की रहने वाली हैं और बाद में मुंबई में रहने लगीं। इस वक्त वो मुंबई में हैं और उनके चार बच्चे हैं। वह साल 2019 में उस समय चर्चा में आईं, जब उन्होंने मिसेज इंडिया अर्थ 2019 प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और विजेता बनीं। उस समय उनकी उम्र करीब 24 साल बताई जाती है। सायली ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की वजह अपने सपनों और आत्मविश्वास को बताया था। उनका कहना था कि इस मंच के जरिए वह अपनी पहचान बनाना चाहती थीं और महिलाओं को अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करना चाहती थीं।

2017 में की थी शादी और इस्लाम धर्म अपनाया

मीडिया से बातचीत में सायली सुर्वे ने बताया कि उनकी मुलाकात कारोबारी आतिफ तासे से एक साझा दोस्त के माध्यम से हुई थी। धीरे-धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और उन्होंने साल 2017 में परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर निकाह कर लिया। सायली का कहना है कि शादी के लिए उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार किया था। हालांकि बाद में उनका आरोप है कि शादी के बाद उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया और रिश्ते में लगातार विवाद, मारपीट और अभद्र भाषा का सामना करना पड़ा। सायली ने अपने अनुभव को 'लव जिहाद' से जोड़ते हुए गंभीर सवाल उठाए हैं। वहीं उनके बयान सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर कई वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, जिनमें दावा किया जा रहा है कि सायली ने बाद में फिर से हिंदू धर्म अपनाने का फैसला किया। बताया जा रहा है कि उन्होंने यह कदम अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उठाया।

RNI No.: UPHIN/25/A1697 Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : ASHWANI KUMAR
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

नेशनल स्किल एंड एजुकेशन समिट का आयोजन, बढ़ेगी युवा शक्ति

उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में नेशनल स्किल एंड एजुकेशन समिट का आयोजन किया. इस दौरान सीएम योगी के सलाहकार अवनीश अवस्थी ने कौशल विकास केंद्रों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर जोर दिया.

(जीएनएस)।

उत्तर प्रदेश में युवाओं को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने और उन्हें उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप कौशल प्रदान करने की दिशा में योगी सरकार लगातार प्रयास कर रही है. इसी उद्देश्य से आज लखनऊ में नेशनल स्किल एंड एजुकेशन समिट का आयोजन किया गया. इसमें सरकार, उद्योग, बैंकिंग, शिक्षण संस्थानों और कौशल विकास से जुड़े विशेषज्ञों ने भाग लिया. समिट में भविष्य की जरूरतों के मुताबिक कार्यबल को तैयार करने पर विचार-विमर्श किया.

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन की ओर से नेशनल स्किल एंड एजुकेशन समिट का आयोजन किया गया. इस अवसर पर समिट में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार युवाओं को आधुनिक और रोजगारपरक कौशल प्रदान करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है.

मजबूत निगरानी व्यवस्था विकसित करना आवश्यक- अवनीश अवस्थी

उन्होंने कहा कि कौशल विकास केंद्रों की गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मजबूत निगरानी व्यवस्था विकसित करना आवश्यक है. इसके लिए प्रत्येक मंडल में सेवानिवृत्त आईएएस, आईपीएस और पीसीएस अधिकारियों, उद्योग विशेषज्ञों तथा बैंकरों की एक समिति गठित करने का सुझाव दिया गया, जो प्रशिक्षण केंद्रों का निरीक्षण कर गुणवत्ता सुनिश्चित करेगी.

उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ अपने सिंगापुर और जापान दौरे का उल्लेख करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी उत्तर प्रदेश की युवा शक्ति और कौशल विकास की संभावनाओं को प्रमुखता से रखा है. साथ ही उन्होंने सभी कौशल केंद्रों की जानकारी, पाठ्यक्रम, छात्रों की संख्या, प्रमाणपत्र और रोजगार की संभावनाओं से संबंधित विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध कराने की सलाह भी दी.

केवल ज्ञान देना पर्याप्त नहीं है- प्रमुख सचिव

समिट के दौरान प्रमुख सचिव डॉ. हरिओम ने कहा कि शिक्षा और कौशल विकास को एक साथ जोड़ना समय की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि केवल ज्ञान देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे व्यवहार में लागू करने की क्षमता विकसित करना भी जरूरी है.

कौशल विकास मिशन के निदेशक पुलकित खरे ने बताया कि प्रदेश में 14 से 35 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को राज्य कौशल योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना और प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत प्रशिक्षण दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण भागीदारों के लिए ग्रेडिंग प्रणाली लागू की गई है और एक डिजिटल लर्निंग पोर्टल भी विकसित किया गया है, जहां युवाओं को मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम और प्रमाणपत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं. प्रदेश में 30 से अधिक क्षेत्रों और लगभग 500 जॉब रोल में प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध है.

कार्यक्रम में हुआ डिजिटल लर्निंग पत्रिका के नए संस्करण का विमोचन

समिट के दौरान उद्योग, शिक्षा और बैंकिंग क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने भी कौशल विकास, रोजगार सृजन और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया. कार्यक्रम में डिजिटल लर्निंग पत्रिका के नए संस्करण का विमोचन भी किया गया.

मेंस्ट्रुअल लीव पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से देश में नई बहस, क्या कानून बनने से महिलाओं के रोजगार पर पड़ेगा असर

(जीएनएस)।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार, 13 मार्च को वर्कप्लेस पर मेंस्ट्रुअल लीव यानि पीरियड लीव को अनिवार्य बनाने की मांग पर सुनवाई करते हुए अहम टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि अगर कानून के जरिए मासिक धर्म के दौरान छुट्टी को अनिवार्य बना दिया गया, तो इसका उल्टा असर पड़ सकता है और कंपनियां महिलाओं को नौकरी देने से कतराने लगेंगी।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर देशभर में महिला कर्मचारियों और छात्राओं के लिए मासिक धर्म के दौरान छुट्टी की व्यवस्था लागू करने की मांग की गई थी। हालांकि, शीर्ष अदालत ने इस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

यह मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ के सामने आया। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि यदि कंपनियां स्वेच्छा से पीरियड लीव देती हैं तो यह एक अच्छी पहल होगी, लेकिन इसे कानून बनाकर अनिवार्य करना महिलाओं के लिए नुकसानदेह हो सकता है।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि जैसे ही इसे कानून के जरिए अनिवार्य किया जाएगा, कई नियोक्ता महिलाओं को नौकरी देने से बचने लगेंगे। अदालत ने कहा, अगर इसे कानून के रूप में अनिवार्य कर दिया गया तो लोग महिलाओं को नौकरी देने से बचेंगे। यहां तक कि न्यायपालिका या सरकारी नौकरियों में भी उन्हें लेने से हिचकिचाहट हो सकती है और उनके करियर पर असर पड़ेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसी मांगों से यह संदेश जा सकता है कि मासिक धर्म महिलाओं के लिए कोई कमजोरी या समस्या है, जबकि यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि कई बार इस तरह की याचिकाएं अनजाने में महिलाओं को कमजोर या कम सक्षम दिखाने का कारण बन सकती हैं।

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के मुख्य बिंदु

नौकरी के कम अवसरः उखक ने

कहा, जिस समय आप कानून में इसे अनिवार्य कर देंगे, कोई भी उन्हें नौकरी नहीं देगा। न्यायपालिका या सरकारी नौकरियों में भी उन्हें लेने से बचा जाएगा। उनका करियर खत्म हो जाएगा कंपनियां कहेंगी कि आप सबको बताकर घर पर ही बैठें।

मानसिकता पर प्रभावः अदालत ने यह भी कहा कि ऐसी कानूनी मांगें महिलाओं को कमजोर या हीन दिखाने का डर पैदा करती हैं, जैसे कि मासिक धर्म उनके साथ कुछ बुरा हो रहा हो।

नियोक्ताओं का पक्षः पीठ ने याचिकाकर्ता से नियोक्ताओं के दृष्टिकोण से भी सोचने को कहा कि उन पर और अधिक PÔid LeÔves का बोझ डालने का क्या परिणाम होगा।

कानून बनाने के लिए सरकार को निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सीधे हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, लेकिन याचिकाकर्ता शैलेंद्र मणि त्रिपाठी को सुझाव दिया कि वे संबंधित अधिकारियों के पास अपनी बात रखें। अदालत ने कहा कि कंपीटेंट अथॉरिटी से सलाह करने के बाद पीरियड लीव पर कानून बनाने पर विचार कर सकते हैं।

हालांकि अदालत ने यह भी कहा कि अगर निजी कंपनियां या संस्थान अपनी इच्छा से महिलाओं के लिए पीरियड लीव की सुविधा देना चाहते हैं, तो यह एक सकारात्मक कदम हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि संबंधित लोग सभी पक्षों से विचार-विमर्श करके इस विषय पर नीति बनाने की संभावना पर विचार कर सकते हैं।

याचिका में क्या मांग की गई थी

यह याचिका शैलेंद्र मणि त्रिपाठी की ओर से दायर की गई थी। इसमें कहा गया था कि देशभर में छात्राओं और कामकाजी महिलाओं के लिए मासिक धर्म के दौरान छुट्टी की नीति लागू की जानी चाहिए। याचिका में यह भी बताया गया कि कुछ राज्यों और संस्थानों ने पहले से ही इस दिशा में कदम उठाए हैं। उदाहरण के तौर पर केरल में स्कूलों में कुछ छूट दी गई है, जबकि कई निजी कंपनियां भी अपनी महिला कर्मचारियों को पीरियड लीव देती हैं।

पहले भी उठ चुका है यह मुद्दा

दरअसल, पीरियड लीव को लेकर देश में काफी समय से बहस चल रही है। समर्थकों का कहना है कि मासिक धर्म के दौरान कई महिलाओं को शारीरिक तकलीफ होती है, इसलिए उन्हें आराम के लिए अलग छुट्टी मिलनी चाहिए। वहीं आलोचकों का तर्क है कि अगर इसे अनिवार्य किया गया तो इससे कार्यस्थल पर महिलाओं के खिलाफ भेदभाव बढ़ सकता है और नियोक्ता पुरुष कर्मचारियों को प्राथमिकता देने लगेंगे।

सुप्रीम कोर्ट इससे पहले वर्ष 2024 में भी इस मुद्दे पर चिंता जता चुका है। तब भी अदालत ने कहा था कि पीरियड लीव को अनिवार्य बनाने से महिलाओं के रोजगार और करियर पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। फिलहाल अदालत ने याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है, लेकिन यह बहस अब भी जारी है कि महिलाओं के स्वास्थ्य और कार्यस्थल पर समान अवसरों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए।

'पिकैक्स माउंटेन' क्या है? जहां ईरान बना रहा है परमाणु बम, क्यों सुपरपावर अमेरिका भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता?

(जीएनएस)।

मध्य-पूर्व में ईरान और इजराइल के बीच छिड़ा संघर्ष अब परमाणु युद्ध की आहट दे रहा है। 14 दिनों से जारी इस जंग में अमेरिका की सीधी एंट्री की संभावना बढ़ गई है। इजराइल द्वारा ईरान के सैन्य ठिकानों पर बमबारी के बाद अब सबकी नजरें ईरान के गुप्त परमाणु ठिकानों पर हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी प्राथमिकता ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना है। इसके लिए ब्रिटेन के एयरबेस पर घातक बमवर्षक विमान तैनात किए जा चुके हैं, जो किसी भी समय ईरान के गहरे बंकरों को निशाना बना सकते हैं।

ईरान का अभेद्य किला

ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को बचाने के लिए जाग्रोस की पहाड़ियों में 'पिकैक्स माउंटेन' नाम का एक बेहद गहरा ठिकाना बनाया है। इसे स्थानीय भाषा में 'कुह-ए कोलांग गाज ला' भी कहा जाता है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्टों के अनुसार, ईरान ने अपना 900 पाउंड से अधिक संवर्धित यूरेनियम यहीं छिपाया है। यह जगह ग्रेनाइट के पहाड़ों के नीचे इतनी गहराई में है कि इसे साधारण मिसाइलों से तबाह करना लगभग नामुमकिन माना जाता है। यहां

लगातार वैज्ञानिक और मशीनें काम कर रही हैं।

नतान्ज के पास बना रहस्यमयी बंकर

यह गुप्त ठिकाना ईरान के मुख्य नतान्ज परमाणु केंद्र से महज 1.6 किलोमीटर दूर स्थित है। जानकारों का मानना है कि यह बंकर जमीन से लगभग 330 फीट (100 मीटर) नीचे बना है, जो ईरान के पुराने 'फोर्डो' प्लांट से भी कहीं अधिक गहरा और सुरक्षित है। इतनी अधिक गहराई और ठोस चट्टानों के कारण पारंपरिक बम इसके ऊपरी हिस्से को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इस ठिकाने को निष्क्रिय करने के लिए विशेषज्ञों का मानना है कि केवल जमीनी सेना की कार्रवाई ही कारगर हो सकती है।

ब्रिटेन में अमेरिकी बमवर्षकों की तैनाती

ईरान के इन गहरे ठिकानों को धस्त करने के लिए अमेरिका ने अपनी रणनीति बदल दी है। ब्रिटेन के आरएएफ फेयरफोर्ड एयरबेस पर तीन घातक B-1B लांसर बमवर्षक विमान तैनात किए गए हैं। ये विमान भारी मात्रा में बम ले जाने और लंबी दूरी तक हमला करने में माहिर हैं। अमेरिका की योजना है कि अगर ईरान परमाणु सीमा लांघता है, तो इन्हीं विमानों के जरिए उसके सबसे सुरक्षित ठिकानों पर निर्णायक प्रहार किया जाएगा ताकि ईरान की परमाणु क्षमता पूरी तरह खत्म हो सके।

यूरेनियम भंडार और परमाणु खतरा

अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) और अमेरिकी अधिकारियों के लिए सबसे बड़ी चिंता ईरान के पास मौजूद 60 प्रतिशत तक संवर्धित यूरेनियम है। लगभग 900 पाउंड की यह मात्रा कई परमाणु बम बनाने के लिए काफी है। हालांकि ट्रंप प्रशासन ने पहले दावा किया था कि यह कार्यक्रम कमजोर हो गया है, लेकिन ईरान ने इसे फिर से तेजी से सक्रिय कर लिया है। जब तक 'पिकैक्स माउंटेन' जैसे ठिकानों को खत्म नहीं किया जाता, तब तक ईरान के परमाणु खतरे को रोकना मुश्किल होगा।

'तू लाख बेवफा है ', कौन हैं टीएमसी सांसद सयानी घोष जिनकी स्पीच ने इंटरनेट पर काटा गदर? लोग दे रहे प्रतिक्रिया

(जीएनएस)।

संसद का बजट सत्र लगातार हंगामे की भेंट चढ़ रहा है, तो वहीं इसी बीच कुछ दिलचस्प बयान और स्पीच लोगों के बीच सुर्खियां भी बन रहे हैं, ऐसा ही एक भाषण इस वक्त सोशल मीडिया पर गदर काट रहा है, जिस पर लोग जबरदस्त ढंग से प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

वो भाषण है ळटउ सांसद सायानी घोष का जो कि उन्होंने एक दिन पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के संदर्भ में दिया था। उन्होंने अपने चुटकीले और शायराना अंदाज से सरकार पर जमकर तंज कसा जो कि वायरल हो गया।

टीएमसी सांसद सयानी घोष ने बुधवार को संसद में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ प्रस्ताव पर चर्चा में कहा कि 'उन्हें खेद है कि उन्हें स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव का समर्थन करना पड़ा, उन्होंने कहा कि मैं बस उनसे यही कहना चाहती हूं कि 'तू लाख बेवफा है सिर उठाकर चल दिल रो पड़ेगा तुझ को पशेमान देख कर।'

'ये सदन है इसे किसी पार्टी का ऑफिस ना बनाएं'

सयानी ने ना केवल अपनी स्पीच में लोकसभा स्पीकर पर तंज कसा बल्कि उन्होंने पीएम मोदी पर भी कटाक्ष किया और कहा कि 'ये सदन है, प्लीज इसे किसी पार्टी का ऑफिस

ना बनाएं।' आपको बता दें कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब सयानी की स्पीच लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी है, इससे पहले भी वो अपने भाषणों के कारण लोगों के बीच सुर्खियां बन चुकी हैं।

'ब्यूटी विद ब्रेन' कहलाती हैं

आपको बता दें कि देखने में बेइंतहा खूबसूरत सयानी घोष को लोग 'ब्यूटी विद ब्रेन' कहते हैं। आपको बता दें कि 27 जनवरी 1993 को जन्मी सयानी बंगाली फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा और नामी चेहरा हैं। उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरूआत टेलीफिल्म 'इच्छे दाना' से की थी।

'नोटोबोर नोटोआउट' फिल्म से शुरू हुआ था करियर

उन्होंने 'कानामाछी', 'अंतराल', 'एकला चलो', 'आमार शहर', 'बिटनूण', 'मायेर बिये' और 'राजकाहिनी' जैसी चर्चित फिल्मों में काम किया है। सांसद सायानी घोष ने साल 2013 और 2014 में 'जलशा मूवीज' पर 'कलकत्ता फुटबॉल लीग' के लाइव प्रसारण के दौरान सह-मेजबानी भी की थी।

जादवपुर सीट से सांसद हैं

सयानी ने 24 फरवरी 2021 को तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन करके अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था, 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में आसनसोल दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र से उन्हें तृणमूल कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित किया गया लेकिनवह इखढ की उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल से हार गईं थीं।

जून 2021 में वो तृणमूल कांग्रेस की युवा शाखा का अध्यक्ष बनी थीं। साल 2024 के भारतीय आम चुनाव में, उन्होंने तृणमूल उम्मीदवार के तौर पर जादवपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की और संसद पहुंचीं।

'मुसलमानों से ज्यादा तो हिंदू मर्द ही', बॉलीवुड की फेमस मुस्लिम एक्ट्रेस का बड़ा बयान, धर्म पर ये क्या कहा?

(जीएनएस)।

महाकुंभ 2025 में रुद्राक्ष की माला बेचकर रातोंरात वायरल हुईं मोनालिसा इस समय अपनी शादी को लेकर लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई हैं। आम लोगों से लेकर सेलेब्स तक इस समय महाकुंभ वायरल गर्ल मोनालिसा को लेकर ही बात करते नजर आ रहे हैं।

महाकुंभ वायरल गर्ल मोनालिसा को लेकर हो रही चर्चा

आपको बता दें कि मोनालिसा की हालिया इंटरफेथ शादी के बाद धर्म और शादी को लेकर बहस फिर तेज हो गई है। इसी बीच 70 के दशक की लिजेंड्री एक्ट्रेस मुमताज ने इंटरफेथ मैरिज और पॉलिगैमी (एक से ज्यादा शादियां) पर खुलकर अपनी राय रखी है।

एक्ट्रेस मुमताज ने दिया बड़ा बयान

अपनी बेबाकी के लिए मशहूर एक्ट्रेस मुमताज ने एक यूट्यूब इंटरव्यू में धर्म, शादी और आध्यात्मिक आस्था से जुड़े कई मुद्दों पर खुलकर बात की है। उन्होंने बताया है कि मुसलमान होने के बावजूद उनकी गहरी आस्था हिंदू देवी-देवताओं में भी है।

धार्मिक आस्था के बारे में ये क्या बोल गईं मुमताज?

-इंटरव्यू में मुमताज ने अपनी धार्मिक आस्था के बारे में बात करते हुए कहा है कि उन्हें भगवान शिव और श्रीकृष्ण से विशेष लगाव है। एक्ट्रेस ने बताया कि वह बचपन से ही इन दोनों देवताओं को बेहद पसंद करती हैं और उनमें उनके प्रति गहरी श्रद्धा रखती हैं।

-मुमताज ने कहा कि उनके घर की सीढ़ियों के पास भगवान गणेश की मूर्ति रखी है और जब भी वह नीचे उतरती हैं तो सबसे पहले उनके चरणों में प्रणाम करती हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि उन्हें हमेशा से सुंदर चीजें पसंद रही हैं और उनके मुताबिक

भगवान शिव बेहद आकर्षक और दिव्य हैं, इसलिए वह उनसे विशेष रूप से जुड़ाव महसूस करती हैं।

मुमताज ने हिंदू बिजनेसमैन से की है शादी

-आपको बता दें कि एक्ट्रेस मुमताज ने उगांडा के मशहूर बिजनेसमैन मयूर माधवानी से शादी की है जो एक हिंदू परिवार से आते हैं। इंटरफेथ मैरिज पर बोलते हुए मुमताज ने कहा कि वह दोनों धर्मों का सम्मान करती हैं। उनका मानना है कि अलग-अलग धर्मों के लोगों के बीच भी सफल और खुशहाल शादी संभव है।

-मुमताज ने बताया कि उनकी बहन ने भी एक हिंदू लड़के से शादी की है और दोनों ही अपने वैवाहिक जीवन में खुश हैं। उनके मुताबिक उनके पति उनका बहुत ख्याल रखते हैं और यही किसी भी रिश्ते की असली नींव होती है।

पॉलिगैमी पर मुमताज का तीखा सवाल

इंटरव्यू के दौरान मुमताज ने मुस्लिम समाज में पॉलिगैमी पर भी अपनी साफ राय रखी। उन्होंने कहा कि कई पुरुष तीन-चार शादियां कर लेते हैं और बाद में अपनी पत्नियों को छोड़ देते हैं। उनके मुताबिक ये बिल्कुल गलत है। मुमताज ने कहा कि वह खुद मुसलमान हैं लेकिन इसके बावजूद मानती हैं कि एक आदमी को बार-बार शादी नहीं करनी चाहिए।

'एक पत्नी को छोड़कर दूसरी से शादी करना गलत'

-मुमताज ने आगे कहा कि किसी एक पत्नी को छोड़कर दूसरी और फिर तीसरी शादी करना सही नहीं है। उनका कहना था कि इस मामले में हिंदू समाज कई बार बेहतर नजर आता है क्योंकि ज्यादातर लोग एक ही शादी निभाने की कोशिश करते हैं।

-मुमताज के मुताबिक कभी-कभी किसी वजह से दूसरी शादी हो सकती है लेकिन ये सही नहीं कि कोई व्यक्ति बार-बार शादी करे और हर बार अपने पुराने रिश्ते को छोड़ दे। मुमताज ने कहा- यही कारण है कि मुझे हिंदू मर्द ज्यादा पसंद हैं जो कि

अमिताभ बच्चन के ऊपर टूटा दुखों का पहाड़, करीबी का हुआ निधन, इमोशनल पोस्ट पढ़ दहल उठेगी आत्मा!

(जीएनएस)।

अमिताभ बच्चन इन दिनों गहरे शोक में हैं। उन्होंने हाल ही में अपने एक बेहद करीबी दोस्त को खोया है। जिसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया और अपने ब्लॉग के जरिए शेयर की। उनकी ये इमोशनल पोस्ट सामने आते ही तेजी से वायरल हो गई और उनके फैंस ने भी संवेदना व्यक्त की।

अमिताभ बच्चन ने अपने निजी ब्लॉग पर एक मार्मिक संदेश लिखते

हुए दोस्त के निधन का जिक्र किया। हालांकि उन्होंने पोस्ट में उस मित्र का नाम या उनके निधन की वजह का खुलासा नहीं किया। अपने शब्दों में उन्होंने बताया कि यह व्यक्ति उनके जीवन में बेहद खास था और उसकी कमी हमेशा महसूस होगी। बिग बी ने लिखा कि उन्होंने एक ऐसे दोस्त को खो दिया है जो बेहद स्नेही, हंसमुख और हर मुश्किल परिस्थिति में मजबूत रहने वाला इंसान था।

"एक-एक कर सब हमें छोड़कर जा रहे हैं"

अपने ब्लॉग में अभिनेता ने लिखा कि उनका दोस्त हर स्थिति में पॉजिटिविटी बनाए रखता था और कठिन से कठिन हालात में भी समाधान ढूंढ लेता था। उन्होंने यह भी कहा कि उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी और यह स्वीकार करना मुश्किल है कि अब वह इस दुनिया में नहीं रहा। अमिताभ बच्चन ने अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए लिखा कि समय के साथ एक-एक कर अपने प्रिय लोगों को खोना बेहद पीड़ादायक होता जा रहा है। पोस्ट के साथ उन्होंने दुख व्यक्त करने के लिए रोने वाला इमोजी भी शेयर किया।

बढ़ती उम्र में ऐसी खबरें सहना मुश्किल

अभिनेता ने यह भी लिखा कि उम्र बढ़ने के साथ इस तरह की दुखद खबरों को स्वीकार करना और भी कठिन हो जाता है। उनके शब्दों से साफ झलक रहा था कि इस क्षति ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया है। अमिताभ बच्चन की इस पोस्ट के सामने आने के बाद उनके फैंस और शुभचिंतकों ने सोशल मीडिया पर उन्हें ढांढस बंधाया। कई लोगों ने कमेंट के जरिए उन्हें मजबूत रहने की सलाह दी और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की।

हाल के समय में झेल चुके हैं कई दर्द

बीते कुछ समय में अमिताभ बच्चन ने अपने जीवन में कई करीबी लोगों को खोया है। इनमें धर्मेंद्र के साथ उनके लंबे समय से जुड़े मित्र और विज्ञापन जगत की जानी-मानी शख्सियत Piyush Pandey का नाम भी शामिल है।

भराड़ीसैंण बजट सत्र से किसानों के लिए आई खुशखबरी, फसल बचाने को केंद्र से मिले 25 करोड़, जानिए किसको होगा फायदा

(जीएनएस)।

उत्तराखंड के किसानों के लिए गैरसेंण के भराड़ीसैंण बजट सत्र से एक राहत देने वाली खबर सामने आई। किसानों की फसल बचाने को केंद्र से 25 करोड़ रुपए मिले हैं। घेर-बाड़ योजना में फिर से केंद्र की मदद शुरू हुई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस मसले पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात की थी।

केंद्र से मदद मिलनी बंद होने पर जिला योजना से प्रदेश काम चला रहा था। इस क्रम में केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने 25 करोड़ रुपए की सहायता

उत्तराखंड के लिए मंजूर की है। बजट सत्र में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने घेर बाड़ योजना के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय से 25 करोड़ की स्वीकृति मिलने की जानकारी सदन में दी।

उन्होंने बताया कि पिछले दिनों गौचर में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने सरकार ने इस विषय को रखा था। अब इस संबंध में केंद्रीय कृषि मंत्रालय के स्तर पर 25 करोड़ की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इस संबंध में मंत्रालय का पत्र विभाग को प्राप्त हो गया है।

क्या है मोजेक डिफेंस? जो बनी ईरान की ताकत, ट्रम्प से पहले ये देश भी टेक चुका है घुटने

(जीएनएस)।

ईरान दशकों से अपनी मोजेक डिफेंस स्ट्रेटजी पर भरोसा करता है। इस रणनीति का आधार मिलिट्री कमांड और कंट्रोल को अलग-अलग करना है। इसका मतलब यह है कि सेना के फैसले केवल एक जगह से नहीं लिए जाते, बल्कि अलग-अलग यूनिट्स को भी काफी हद तक फैसले लेने की छूट होती है। इसी वजह से अमेरिका और इजरायल जैसे देशों द्वारा किए जाने वाले लीडरशिप टारगेट या डिकैपिटेशन स्ट्राइक का असर कम हो जाता है। इसके साथ ही ईरान युद्ध को लंबा खींचने के लिए आर्थिक दबाव और बेहिसाब लागत जैसी रणनीतियों का भी इस्तेमाल करता है।

'हम मोजेक स्ट्रेटजी तय करेगी कब खत्म होगा युद्ध'

1 मार्च 2026 से अमेरिका और इजरायल द्वारा चलाए गए Operation Epic Fury के दौरान ईरान के विदेश मंत्री Seyed Abbas Araghchi ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि ईरान ने पिछले दो दशकों में अमेरिकी सेना की हार का गहराई से अध्ययन किया है। उनके मुताबिक, "कैपिटल पर बमबारी हमारी युद्ध क्षमता को खत्म नहीं कर सकती। हमारी टुकड़ों में बंटी मोजेक डिफेंस स्ट्रेटजी हमें यह तय करने देती है कि युद्ध कब और कैसे खत्म होगा।"

ए७स्र'ल्लीि

कैसे काम करती है ये स्ट्रेटजी?

अराघची के मुताबिक इस रणनीति के दो हिस्से होते हैं। पहला, अमेरिकी सैन्य कमजोरियों का लगातार अध्ययन करना और उसके मुताबिक अपनी रणनीति बदलना। दूसरा, कमांड और कंट्रोल को पूरी तरह से अलग-अलग कर दिया जाता है ताकि अगर नेतृत्व पर हमला भी हो जाए तो युद्ध जारी रह

भारतीय राजस्व सेवा (आयकर) के 79वें बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों ने उपराष्ट्रपति से भेंट की

ह्रराजस्व सेवा अधिकारी राष्ट्र की वित्तीय शक्ति के संरक्षक हैंह्व: उपराष्ट्रपति

ह्रईमानदार करदाता देश की असली ताकत और सच्चे देशभक्त हैंह्व: उपराष्ट्रपति

उपराष्ट्रपति ने आईआरएस प्रशिक्षु अधिकारियों से निष्पक्ष और पारदर्शी कर प्रशासन सुनिश्चित करने का आह्वान किया

प्रविष्टि तिथि: 13 टअफ 2026 7:36ढट ु८ ढक्ह ऊ

"भारतीय राजस्व सेवा (आयकर) के 79वें बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों ने आज उपराष्ट्रपति भवन में उपराष्ट्रपति श्री सी. पी. राधाकृष्णन से भेंट की।

प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने राजस्व सेवा के अधिकारियों को राष्ट्र की वित्तीय शक्ति का संरक्षक बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि देश भर में विकास कार्य तभी संभव हैं, जब करों के माध्यम से राजस्व प्राप्त हो। उन्होंने कहा कि जहाँ एक ओर यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि कर की चोरी न हो, वहीं अधिकारियों को यह भी देखना चाहिए कि करदाताओं को किसी भी प्रकार की अनावश्यक असुविधा का सामना न करना पड़े।

उपराष्ट्रपति ने आगे कहा कि अवैध आय की पहचान की जानी चाहिए, जबकि ईमानदारी और कानूनी तरीके

से की गई कमाई की सराहना होनी चाहिए।

उन्होंने उल्लेख किया कि कर प्रशासन और भुगतान में प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग जैसे सुधारों के बावजूद, कुछ लोग अभी भी करों की चोरी के लिए सिस्टम में हेरफेर करने का प्रयास कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ऐसे मामलों का पता लगाना और यह सुनिश्चित करना कि देय कर का भुगतान किया जाए, कर अधिकारियों का कर्तव्य है।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत तेजी से प्रगति कर रहा है, जहाँ बड़े पैमाने पर संपत्ति का सृजन हो रहा है, बुनियादी ढांचा मजबूत हो रहा है और ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में विकास आगे बढ़ रहा है। उन्होंने उल्लेख किया कि आर्थिक विकास के साथ जैसे-जैसे राजस्व बढ़ता है, राजस्व अधिकारियों की भूमिका और जिम्मेदारी और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। ईमानदार करदाताओं को सच्चे देशभक्त बताते हुए उन्होंने कहा कि उनके साथ हमेशा सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए।

भारत की सुशासन की समृद्ध परंपरा का उल्लेख करते हुए, उपराष्ट्रपति ने कौटिल्य की शिक्षाओं का उदाहरण दिया, जिन्होंने परामर्श दिया था कि कर संग्रहण मधुमक्खियों के कार्य की तरह होना चाहिए, जो फूलों को ताजा छोड़ते हुए केवल उचित मात्रा में ही रस एकत्र करती हैं। उन्होंने आगे कहा कि अत्यधिक टैक्स दरों के वे दिन अब बीत चुके हैं, जब व्यक्तिगत आय पर 90 प्रतिशत से अधिक की दर से कर लगाया जाता था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि टैक्स प्रणाली पारदर्शी, निष्पक्ष और करदाता-अनुकूल होनी चाहिए, जबकि कर चोरी से पूरी सख्ती के साथ निपटा जाना चाहिए।

उपराष्ट्रपति ने 'सेवा तीर्थ' के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कहे उन शब्दों को भी याद किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि ह्रसेवा की भावना भारत की आत्मा और इसकी असली पहचान है।ह्व उन्होंने उल्लेख किया कि 'सेवा तीर्थ' का नाम नागरिकों की सेवा के एक पवित्र स्थान के रूप में रखा गया है। साथ ही, उन्होंने प्रशिक्षु अधिकारियों से ह्रसेवा परमो धर्म:ह्व (सेवा ही परम कर्तव्य है) के मार्गदर्शक सिद्धांत का पालन करने का आह्वान किया।

यह रेखांकित करते हुए कि आईआरएस अधिकारियों को भविष्य में डिजिटल लेनदेन, वैश्विक उद्यमों, क्रिप्टोकरेंसी और सीमा पार वित्तीय संरचनाओं जैसे जटिल मुद्दों से निपटना होगा, उन्होंने आजीवन सीखते रहने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने प्रशिक्षु अधिकारियों को सरकार के क्षमता विकास मंच, आईगॉट का पूरा उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया।

एनएक्सटी 2026 सम्मेलन नीतिगत चचाओं, नवाचार और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभर रहा है: लोकसभा अध्यक्ष

(जीएनएस)।

नई दिल्ली में आयोजित एनएक्सटी कॉन्क्लेव 2026 में भाग लेने आए 30 से अधिक देशों के सांसदों, उद्योगपतियों और विचारकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला से मुलाकात की। इस अवसर पर श्री बिरला ने संसद भवन में विभिन्न लोकतांत्रिक देशों के जन प्रतिनिधियों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की मेजबानी के दौरान प्रसन्नता व्यक्त की और वैश्विक संसदीय संवाद के महत्व पर प्रकाश डाला।

श्री बिरला ने राज्यसभा सांसद श्री कार्तिकेय शर्मा की एनएक्सटी 2026 सम्मेलन की पहल की सराहना की, जो नीतिगत चचाओं, नवाचार और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभर रहा है।

श्री बिरला ने कहा कि यह सम्मेलन समकालीन वैश्विक चुनौतियों और अवसरों पर विचार-विमर्श करने के लिए विश्वभर के सांसदों, नीति निमार्ताओं और विचारकों को एक साथ लाता है।

भारत की लोकतांत्रिक विरासत पर प्रकाश डालते हुए, श्री बिरला ने कहा कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत को अक्सर "लोकतंत्र की जननी" कहा जाता है, जो देश की संवाद, आम सहमति और सहभागी निर्णय लेने की लंबी परंपरा को दशार्ता है। श्री बिरला ने इस बात पर जोर दिया कि भारत की संसद 140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं और विविधता का प्रतिनिधित्व करती है, जहां विभिन्न दृष्टिकोणों के बीच बहस और संवाद के माध्यम से नीतियां निर्धारित की जाती हैं।

श्री बिरला ने पिछले एक दशक में समावेशी विकास, डिजिटल नवाचार और सुशासन में भारत की प्रगति पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी आधारित शासन, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने सार्वजनिक प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को काफी मजबूत किया है ।

श्री बिरला ने डिजिटल संसद, बेहतर संसदीय अनुसंधान प्रणालियों और आधुनिक सूचना प्लेटफार्मों जैसी पहलों के माध्यम से संसदीय प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लाभ उठाने पर भारत के फोकस पर प्रकाश डाला।

साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की सतर्कता-आधारित पहल 'प्रयास' ने 846 विधवाओं और आश्रितों के लिए पीएफ व पेंशन का समय पर निपटारा सुनिश्चित किया

(जीएनएस)।

मृतक कर्मचारियों के परिवारों को समय पर सामाजिक सुरक्षा लाभ सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) ने अप्रैल 2025 से अब तक एसईसीएल के सतर्कता विभाग, मानव संसाधन विभाग और कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ) के बीच समन्वित प्रयासों के माध्यम से 846 भविष्य निधि (पीएफ) और पेंशन मामलों का सफलतापूर्वक निपटारा किया है।

इस पहल से मुख्य रूप से उन विधवाओं और मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को लाभ मिला है, जिन्हें

अक्सर प्रक्रियागत जटिलताओं के कारण पेंशन और पीएफ लाभ प्राप्त करने में देरी का सामना करना पड़ता है। प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके और विभिन्न एजेंसियों के बीच तालमेल को बेहतर करके एसईसीएल ने ऐसे दावों के निपटारे की गति को काफी तेजी किया है।

देरी की समस्या को दूर करने के लिए सतर्कता विभाग की पहल

मामलों के निपटारे में देरी के कारण परिवारों को होने वाली कठिनाइयों को देखते हुए, एसईसीएल के सतर्कता विभाग ने 5 अप्रैल, 2025 को औपचारिक रूप से सीएमपीएफओ और प्रबंधन के समक्ष यह मुद्दा उठाया। साथ ही, लंबित मामलों को समय-सीमा के भीतर सुलझाने के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर दिया।

इस पहल के बाद, 22 अप्रैल, 2025 को एक संयुक्त समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें एसईसीएल प्रबंधन, सीएमपीएफओ के अधिकारियों और विभिन्न कार्यक्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान, लंबित मामलों की एक-एक करके समीक्षा की गई और उनके निपटारे में तेजी लाने के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए गए। मामले की स्थिति को ट्रैक करने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक मासिक निगरानी तंत्र भी शुरू किया गया।

राष्ट्रपति भवन ने 'पर्पल फेस्ट' का आयोजन किया

हम 2047 तक 'विकसित भारत' के सामूहिक लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर हैं और दिव्यांगजन इस यात्रा में समान भागीदार हैं: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु

(जीएनएस)।

दिव्यांगजनों की प्रतिभा, उपलब्धियों और आकांक्षाओं का जश्न मनाने के लिए आज (13 मार्च, 2026) राष्ट्रपति भवन में 'पर्पल फेस्ट' का आयोजन किया गया। दिन भर चले इस उत्सव में 8,000 से अधिक दिव्यांगजनों ने अमृत उद्यान का दौरा किया, जो आज खास तौर पर उनके लिए खोला गया था। उन्होंने दिव्यांगजनों के लिए काम करने वाले विभिन्न संगठनों द्वारा लगाए गए स्टालों के जरिए कई मनोरंजक खेलों और सीखने की गतिविधियों में भी भाग लिया।

शाम को, भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने समारोह में शिरकत की और राष्ट्रपति भवन के खुले रंगमंच में दिव्यांगजनों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आनंद लिया।

इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि किसी भी देश या समाज की पहचान केवल उसके विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों के लिए हासिल की गई

कामयाबियों से नहीं, बल्कि हाशिए पर रहने वाले लोगों के प्रति उसकी संवेदनशीलता से होती है। अगर हम भारतीय इतिहास पर नजर डालें, तो दखेंगे कि संवेदनशीलता, समावेशिता और सद्भाव में विश्वास हमारी संस्कृति और सभ्यता के मूल तत्व रहे हैं। भारत का संविधान हमें आदर्श सामाजिक मानक प्रदान करता है। हमारे संविधान की प्रस्तावना सामाजिक न्याय, सामाजिक समानता और व्यक्ति की गरिमा के आदर्शों को स्थापित करती है। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत दिव्यांगजनों को शिक्षा, कार्य और सार्वजनिक सहायता का अधिकार प्रदान करते हैं।

राष्ट्रपति ने कहा कि समावेशी समाज के निर्माण के लिए दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण बेहद जरुरी है। हालांकि, यह केवल सरकार की कोशिशों से संभव नहीं है। इसके लिए समाज के हर व्यक्ति और संस्था की सक्रिय भागीदारी जरुरी है।

राष्ट्रपति ने कहा कि हम वर्ष 2047 तक 'विकसित भारत' के सामूहिक लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और दिव्यांगजन इस यात्रा में समान भागीदार हैं। समाज के हर सदस्य का यह फर्ज.है कि उन्हें समान अवसर और सम्मान के साथ प्रगति करने का अवसर दिया जाए।

राष्ट्रपति ने कहा कि दिव्यांगजनों को आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उन्हें इस यात्रा में सरकार और समाज का पूरा सहयोग मिलेगा। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों का समर्पण, मेहनत और लगन न केवल उनके लिए सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगी, बल्कि बाकी नागरिकों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनेगी।

भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित 'पर्पल फेस्ट' का मकसद विभिन्न प्रकार की शारीरिक बाधाओं और उनके लोगों के जीवन पर पड़ने वाले असर के बारे में जागरूकता बढ़ाना और समाज में दिव्यांगजनों के प्रति समझ, स्वीकृति और समावेश को बढ़ावा देना है।

आयुष अनुसंधान में नैतिक समीक्षा के लिए एक नया मानदंड स्थापित करते हुए, सीसीआरएएस की केंद्रीय नैतिकता समिति (सीईसी सीसीआरएएस) का एसआईडीसीईआर-एफईआरसीएपी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मूल्यांकन किया गया

(जीएनएस)।

भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के तहत केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसन्धान परिषद् (सीसीआरएएस) की केंद्रीय नैतिकता समिति (सीईसी) का 9 से 12 मार्च 2026 तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नैतिकता प्रत्यायन निकाय - एशियाई और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में नैतिक समीक्षा समितियों के मंच (एफईआरसीएपी) के तत्वावधान में रणनीतिक नैतिक समीक्षा क्षमता विकास पहल (एसआईडीसीईआर) द्वारा बाहरी मूल्यांकन किया गया।

सर्वेक्षण दल में दो अंतरराष्ट्रीय सर्वेक्षक और तीन भारतीय सर्वेक्षक शामिल थे, जिन्होंने समिति की नैतिक समीक्षा प्रक्रियाओं और परिचालन मानकों का व्यापक मूल्यांकन किया।

एसआईडी सीईआर-एफईआरसीएपी फाउंडेशन अंतरराष्ट्रीय सहयोग और क्षमता निर्माण के माध्यम से स्वास्थ्य

अनुसंधान के नैतिक आचरण को सुदृढ़ करने के लिए समर्पित है। इसकी कठोर मूल्यांकन प्रक्रिया नैतिकता समितियों को वैश्विक, राष्ट्रीय और स्थानीय मानकों के अनुरूप परखती है, जिससे निरंतर गुणवत्ता सुधार को बढ़ावा मिलता है और मानव अनुसंधान प्रतिभागियों की सुरक्षा बढ़ती है।

अब तक, समकालीन चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित 17 भारतीय संस्थानों की समीक्षा एसआईडीसीईआर-एफईआरसीएपी सर्वेक्षण टीम द्वारा की जा चुकी है। विशेष रूप से, सीसीआरएएस की केंद्रीय आचार समिति आयुष क्षेत्र से इस प्रतिष्ठित मूल्यांकन को करने वाली पहली नैतिकता समिति बन गई है।

यह महत्वपूर्ण पहल सीसीआरएएस की नैतिक समीक्षा प्रक्रियाओं की गुणवत्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही को और बेहतर बनाने की प्रतिबद्धता को दशार्ती है। उम्मीद है कि इस प्रयास से आयुष अनुसंधान प्रणाली में नैतिकता के शासन के मानकों को अंतरराष्ट्रीय स्तर तक ऊंचा उठाया जाएगा और यह अन्य प्रमुख आयुष संस्थानों के लिए एक अनुकरणीय मॉडल के रूप में कार्य करेगा।

केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी की अध्यक्षता में कोयला मंत्रालय की परामर्श समिति की बैठक का आयोजन

(जीएनएस)।

केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी की अध्यक्षता में कोयला मंत्रालय से संबद्ध सांसदों की परामर्श समिति की बैठक गुरुवार को आयोजित की गई। कोयला एवं खान राज्य मंत्री श्री सतीश चंद्र दुबे, समिति के सदस्य, कोयला मंत्रालय और कोयला कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।

इस बैठक में कोयला मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने 'कोयला कंपनियों में प्रौद्योगिकी उन्नयन' पर प्रमुख नीतिगत पहलों, प्रगति और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की।

कोयला मंत्रालय के सचिव श्री विक्रम देव दत्त ने सभी गणमान्य व्यक्तियों और समिति के सदस्यों का स्वागत किया। श्री दत्त ने बताया कि वर्तमान में देश में कोयले की अभूतपूर्व मांग नहीं है।

कोयला और खान राज्य मंत्री श्री सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि कोल इंडिया खनन, अनुसंधान और विकास तथा कोयला गैसीकरण के क्षेत्रों में काम कर रही है।

श्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि वर्तमान परिदृश्य में प्रौद्योगिकी उन्नयन

केवल एक अवसर नहीं बल्कि एक स्थायी लक्ष्य बन गया है। उन्होंने कहा कि सरकार उत्पादन, सुरक्षा, दक्षता और पर्यावरण संबंधी उत्तरदायित्व सहित कोयला क्षेत्र के सभी पहलुओं को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। श्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में कोयला क्षेत्र में क्रांतिकारी तकनीकी परिवर्तन हो रहा है। सर्वेक्षण में ड्रोन प्रौद्योगिकी के उपयोग, 3डी लेजर स्कैनिंग, एआई और मशीन लर्निंग आधारित भविष्यसूचक विश्लेषण यह क्षेत्र पारंपरिक खनन से स्मार्ट, सुरक्षित और डिजिटल खनन की ओर अग्रसर हो रहा है।

श्री जी किशन रेड्डी ने समिति को कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, बायोमास कोफायरिंग और कोल गैसीफिकेशन जैसी उन्नत तकनीकों को अपनाने के लिए मंत्रालय के प्रयासों से अवगत कराया। उन्होने कहा कि निरंतर नवाचार और प्रौद्योगिकी का एकीकरण ही कोयला क्षेत्र का भविष्य है।

कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष श्री बी. साईराम ने बताया कि सीआईएल अपने सभी परिचालनों में प्रौद्योगिकी का व्यापक उन्नयन कर रही है। इसमें अन्वेषण के लिए 3डी भूकंपीय सर्वेक्षण और ड्रोन जैसे उन्नत उपकरणों का उपयोग, और दक्षता और सुरक्षा बढ़ाने के लिए निरंतर खनन मशीनें और हाईवॉल प्रणाली जैसे आधुनिक उपकरण शामिल हैं। कंपनी कोयला परिवहन को बेहतर बनाने और इसके पर्यावरण पर प्रभाव को कम करने के लिए नए रेलवे कॉरिडोर और कन्वेयर सिस्टम के साथ-साथ बुनियादी ढांचे में भी सुधार कर रही है। एसएपी ईआरपी और 5जी-सक्षम आईओटी सिस्टम जैसी पहलों के माध्यम से डिजिटल परिवर्तन को गति दी जा रही है। सीआईएल शीर्ष भारतीय संस्थानों के साथ अनुसंधान और सहयोग के माध्यम से स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों और सतत खनन पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

बैठक में बताया गया कि नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन ने प्रौद्योगिकी उन्नयन और व्यापक डिजिटलीकरण पहलों के माध्यम से अपने संचालन में उल्लेखनीय प्रगति की है। सभी नेवेली परिसरों और बाहरी परियोजनाओं में भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण के लिए डैशबोर्ड और कोयले की आपूर्ति की निगरानी और प्रबंधन के लिए डिजिटल लॉजिस्टिक प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है। इन पहलों में ओआईटीडीएस और जियो-फेंसिंग तकनीक के माध्यम से निगरानी और खानों के कुशल सर्वेक्षण के लिए स्थलीय 3डी लेजर स्कैनर और ड्रोन का उपयोग शामिल है। एनएलसी ने चोरी और दुरुपयोग को रोकने के लिए एक ईंधन प्रबंधन प्रणाली भी लागू की है।

बैठक में समिति को जानकारी दी गई कि सिंगारेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड के तकनीकी उन्नयन तथा प्रमुख परिचालन सुधारों में एकीकृत नियंत्रण एवं कमांड सेंटर, 3डी लेजर स्कैनिंग, डीजीपीएस और ड्रोन आधारित जीआईएस सर्वेक्षण शामिल हैं। इंटेलिजेंट कोल लॉजिस्टिक्स डैशबोर्ड, विजुअल मॉनिटरिंग सिस्टम और 410 से अधिक डंपरों में सुरक्षा उपकरणों के माध्यम से लॉजिस्टिक्स में सुधार किया जा रहा है। समिति के सदस्यों को कोयला खान भविष्य निधि संगठन की तकनीकी पहलों के बारे में भी जानकारी दी गई।

समिति के सदस्यों ने मंत्रालय के सक्रिय प्रयासों की सराहना की और प्रौद्योगिकी उन्नयन के माध्यम से कोयला कंपनियों में उत्पादन के इष्टतम तरीके अपनाने के सुझाव दिए।

केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को एग्रीनोवेट इंडिया लि. ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ₹3.40 करोड़ का लाभांश अदा किया

(जीएनएस)।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को आज दिल्ली में एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ₹3,39,97,362 का लाभांश अदा किया। एग्रीनोवेट इंडिया लि., कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (DARE), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन भारत सरकार का एक नवरत्न उपक्रम है। यह वितरण निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया गया है।

इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एग्रीनोवेट इंडिया, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) की सृजनात्मक क्षमता और किसानों की व्यावहारिक आवश्यकता के बीच एक सशक्त पुल का कार्य कर रहा है। कृषि नवाचारों के हस्तांतरण और तकनीकी उद्यमिता को बढ़ावा देने में संस्थान का योगदान सराहनीय है। यह आत्मनिर्भर भारत के कृषि लक्ष्य को सशक्त करने वाली पहल है।मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ प्रवीण मलिक ने कहा कि यह लाभांश कंपनी की वित्तीय सुदृढ़ता, सुशासन और निरंतर नवाचार के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दशार्ता है।

कार्यक्रम में एग्रीनोवेट इंडिया लि. के अध्यक्ष एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (क्उअफ) के महानिदेशक डॉ. एम.एल. जाट तथा गैर-सरकारी निदेशक श्री आनंद मोहन अवस्थी उपस्थित थे।

2011 में स्थापित, एग्रीनोवेट इंडिया लि., कउअफकी व्यावसायिक शाखा के रूप में कार्य करती है।